

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वागेश्वर।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून दिनांक: ११ / दिसम्बर / 2008

विषय:-श्री दिलीप जावलकर पुत्र श्री राजाराम जावलकर एवं श्रीमती सौजन्या पत्नी श्री दिलीप जावलकर, निवासी-कावलानामा, तहसील करबीर, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र जो वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत शासकीय सेवा में है, को कौसानी स्टेट, तहसील गरुड, जिला-वागेश्वर में आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि क्रय की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-409/रटाम्प-भू-क्रय/2008 दिनांक-22 अगस्त, 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्री दिलीप जावलकर पुत्र श्री राजाराम जावलकर एवं श्रीमती सौजन्या पत्नी श्री दिलीप जावलकर, निवासी-कावलानामा, तहसील करबीर, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र जो वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत शासकीय सेवा में है, को आवासीय प्रयोजन हेतु कौसानी स्टेट, तहसील गरुड, जिला-वागेश्वर में कुल 0.140 हे०(रात नाली) भूमि क्रय की अनुमति उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15.12.2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत आपके उपरोक्त पत्र को द्वारा अनुमोदित/संस्तुत सरास संख्या-787740, 7929, 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 एवं 7936 से क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- क्रेता धारा-129-स के अर्धीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि क्रेता या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारी से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- केंद्रों द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय बिलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, चररी प्रयोजन (निजी आवास) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके मूख्यगी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हो और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके मूख्यगी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हो।

6- शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7- प्रस्तावित भूमि का उपयोग केवल निजी आवास के उपयोग हेतु ही किया जायेगा, तथा किसी भी स्थिति में उक्त का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जायेगा।

8- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सरकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

9- कय की गयी भूमि पर निर्माण कार्य किये जाते समय राज्य की प्रचलित भूमि विनियम/नियम विधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुरार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

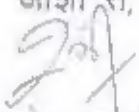
(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ०प०सं०-१११ / रांगदिनांकत / 2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुरारि राजरत्न आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त, कुमायूं मण्डल नैनाताल।
- 3- श्री दिलीप जावलकर पुत्र श्री राजाराम जावलकर तत्कालीन जिलाधिकारी बागेश्वर हाल जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग एवं श्रीमती सौजन्या पत्नी श्री दिलीप जावलकर हाल जिलाधिकारी टिहरी।
- 4- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, राधिकालय।
- 5- प्रभारी मीडिया सेंटर, राधिकालय।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(सन्तोष यदोनी)
अनुराधिप।